

[श्री सत्यनारायण जटिया]

मिलों की स्थिति भी ठीक नहीं है। विनोद और बिमल टैक्सटाइल मिल्स के 362 सेवा निवृत्त कर्मचारियों की भविष्य निधि 17 लाख 72 हजार का भुगतान अब तक नहीं किया गया है।

सिंथेटिक पालिस्टर और नायलोन यार्न के उत्पादक श्री सिंथेटिक्स लिमिटेड, उज्जैन ने कर्मचारियों को वर्ष 1982-83 के बोनस की अदायगी नहीं की है। कारखाने ने एक जुलाई, 1982 से 30 जून, 1983 को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष में 114.65 लाख रुपयों का शुद्ध मुनाफा अर्जित किया है। प्रबन्धक "नोटिस आफ चेन्ज" दिये बिना ही बोनस अदायगी के साथ "वर्कलोड" की 95 शर्तों को जोड़ने के लिये आमादा हैं और मजदूरों को बोनस नहीं देना चाहते हैं। विगत 1979-80, 1980-81, 1981-82 के वर्षों में न्यूनतम बोनस पर "एक्सग्रेसिया" दिया गया है जबकि कानूनन अधिकतम बोनस पर "एक्सग्रेसिया" दिया जाना चाहिये। वर्ष 1982-83 की बैलेंस-शीट में 1393.08 लाख का "डिप्रोसियेशन" दर्शाया गया है जबकि कारखाने की स्थापना लागत 10 करोड़ रुपये है। वर्ष 1982-83 में कर्मचारियों के "वेलफेयर" की मद में 23.67 लाख व्यय दर्शाया गया है किन्तु कर्मचारियों के लिए उक्त राशि व्यय नहीं की गई है।

अतएव केन्द्र सरकार उक्त स्थितियों में देश में और मध्य प्रदेश में उक्त उद्योगों में कार्यरत हजारों श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिये इन्दौर के होप टैक्सटाइल्स को शीघ्र प्रारम्भ करे। उज्जैन की टैक्सटाइल्स मिलों की वर्तमान स्थिति में सुधार करे। सेवा निवृत्त श्रमिकों को भविष्य निधि का भुगतान करे तथा श्री सिंथेटिक्स के कर्मचारियों को तत्काल कानूनन बोनस भुगतान करने के निर्देश प्रदान करे।

(ii) Need to start air service between
Delhi-Khajuraho-Aurangabad-Bhopal-
Bombay

श्री प्रताप भानु शर्मा (विदिशा) : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश देश का सबसे विशाल प्रदेश है

तथा केन्द्र सरकार ने प्रदेश में पर्यटन विकास के लिये 14 प्रमुख पर्यटन एवं धार्मिक केन्द्रों का चयन किया है परन्तु पर्यटकों को आवागमन की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण अधिक संख्या में पर्यटक इन स्थलों का भ्रमण नहीं कर पाते हैं। विगत कई वर्षों से मध्य प्रदेश शासन एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा बम्बई, औरंगाबाद, भोपाल, खजुराहो एवं दिल्ली के बीच एक नई वायु सेवा प्रारम्भ करने की मांग की जा रही है।

इन्डियन एयर लाइन्स द्वारा पूर्व में बम्बई, औरंगाबाद, नागपुर, खजुराहो वायुसेवा 7 महीनों के लिए शुरू की गई थी परन्तु इस सम्बन्ध में पूर्व प्रचार-प्रसार न होने के कारण वायुसेवा लाभप्रद नहीं हुई और उसे बन्द करना पड़ा।

केन्द्र एवं मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन-प्रोत्साहन के लिए हर सम्भव प्रयास कर रही है। यदि मध्य प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देना है तो यहां उक्त वायुसेवा को अतिशीघ्र प्रारम्भ करना आवश्यक है ताकि दिल्ली से आने वाले पर्यटक खजुराहो देखने के पश्चात् सांची एवं मांडू का भ्रमण कर बम्बई जा सकें। अतः केन्द्रीय नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध है कि दिल्ली, खजुराहो, भोपाल, औरंगाबाद एवं बम्बई के बीच नई वायुसेवा के संचालन हेतु त्वरित कार्यवाही करें।

12.21 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

(iii) Need to develop alternative sources of energy for boosting afforestation schemes in the country, especially in the Aravali hills range

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के तहत देश के सबसे वयोवृद्ध पर्वत अरावली पर आये गम्भीर संकट की तरफ कृषि मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। इस पर्वत का अधिकांश भाग राजस्थान के हिस्से में है। राजस्थान में देश की 10 प्रतिशत भूमि है पर दुर्भाग्य से देश में पानी का केवल 1 प्रतिशत भाग वहां है। इसलिए बूंद-बूंद जल वहां

के मनुष्यों, पशुओं तथा वनस्पति के लिए बहुमूल्य है। वनों के लिए पानी कम मिलने से पुनः पेड़ लगाना मुश्किल हो जाते हैं। उधर अरावती पर्वत की बेरहमी से कटाई हो रही है। उन्नत देशों में 1/3 भाग में जंगल होते हैं। हमारे देश में इसका प्रतिशत कम है पर राजस्थान में तो केवल 10 प्रतिशत आंकड़ों में है। अभी हाल ही में कोस्मो-नोट्स ने बताया कि केवल 3 प्रतिशत भाग में (राजस्थान) जंगल हैं अर्थात् इतनी अधिक कटाई हुई है। बड़े-बड़े पेड़ों के साथ नये उगते पेड़ भी ठेकेदारों की कुल्हाड़ी से नहीं बचे। नंगा अरावली पर्वत ठेकेदारों की क्रूरता का स्मारक बन गया है। सारा अरावली भूभाग एक पथरीले रेगिस्तान में बदलने की सम्भावनायें खड़ी हो गयी हैं।

अतः मैं सरकार से मांग करूंगी कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस पर्वत के संरक्षण एवं पुनः वनारोपण के लिए विशेष कार्यक्रम बनाने के लिए हरियाणा के साथ राजस्थान को भी विशेष आर्थिक सहायता दी जावे।

वनों की अवैध तथा वैध कटाई तथा तस्करी के लिये विशेष कदम उठाये जायें।

ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के लिये जैसे बायो गैस तथा सौर्य ऊर्जा आदि को लोकप्रिय बनाने के लिये और अधिक अनुदान सभी को दिया जावे तभी हम हमारे अतीत के गौरव भविष्य की आशा तथा सुरक्षा अरावली पर्वत को पुनः हरा-भरा बना सकेंगे।

(iv) **Need for immediate allotment of alternative land to families displaced due to Kallada Irrigation Project**

SHRI K. KUNHAMBU (Cannanore) : Sir, the Kallada Irrigation Project in Kerala is nearing completion. With the completion of this Project, a large part of the forest area will be under water, and about 300 families living in that area will have to be evacuated. Anticipating this, the Govern-

ment of Kerala discussed this problem with the representatives of the settlers in 1977 and 1978 and finally in 1981. After the discussion, it was decided that the people who would be displaced would be resettled in a place called Kalluvettam Kuzhi in the Punalur forest division. Accordingly the forest in this area has been cleared. But no further step has been taken to allot this land to them.

It is understood that the main hurdle in allotting the land is the new Forest Act of the Centre under which clearance from the Centre is required to be obtained before allotment of forest land.

As a matter of fact, forest in the above-mentioned place was cleared long before the new Forest Act came into force and, therefore, this area should be exempted from the operation of the Act.

As the Project is nearing completion, water level in the area is constantly rising. More than 60 families have already been evacuated to temporary shelters.

Therefore, I would request the Government to immediately give clearance for the allotment of this land.

(v) **Need to declare the Bhanj Puran tribe of Orissa a Scheduled Tribe.**

SHRI MANMOHAN TUDU (Mayurbhanj) : Bhanj Puran Tribe living extensively in Mayurbhanj district, Orissa is very much neglected. Government of India has taken several steps for the all round development of SC, ST and other weaker sections of the society. But the condition of Bhanj Puran Tribe is getting worse day by day. The total population of this Tribe is 5 lakhs in Orissa out of which 3 lakhs are living in Mayurbhanj.

They have been agitating for the last several years to include them in the S.T. list.

A representation had been submitted before the S.C. and S.T. Commission by Bhanj Puran Tribe to include them as S.T. As these people are poor and illiterate, the